5 दिन चलेगा सफदरजंग अस्पताल में पैलिएटिव केयर क्लीनिक। यहां गंभीर मरीजों के दर्द का इलाज होगा। फिलहाल अस्पताल में सप्ताह में तीन दिन इसकी ओपीडी होती है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 12 अक्टूबर 2019

कीर्ति आजाद होंगे दिल्ली कांग्रेस के कप्तान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार शाम दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि एक-दो दिन में पार्टी आलाकमान की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी।

20 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के निधन के बाद खाली हुए पद पर पार्टी लंबे समय से किसी योग्य नेता का नाम तलाशने में जुटी हुई थी। सोनिया गांधी के साथ प्रदेश प्रभारी पीसी चाको की कई बार अध्यक्ष चुने जाने को लेकर बैठक हुई। इस दौरान सभी पूर्व अध्यक्षों व तीनों मौजूदा कार्यकारी अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई। बीच में शत्रुघ्न सिन्हा और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी उछला, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के चलते किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष ने मौजूदा स्थिति को 1998 की स्थिति के समकक्ष पाया। उस समय भी प्रदेश कांग्रेस भारी गुटबाजी से जूझ रही थी। उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान बाहर से लाकर शीला दीक्षित को सौंपी गई थी।

कीर्ति आजाद

> आला कमान ने कुछ कारणों से एक-दो दिन के लिए औपचारिक घोषणा रोकने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। नए अध्यक्ष के तौर पर कीर्ति के नाम के बदले जाने की संभावना नहीं के बराबर है।
> **-पीसी चाको, प्रदेश प्रभारी, दिल्ली कांग्रेस**

कीर्ति आजाद का नाम बुधवार शाम को सोनिया गांधी, पीसी चाको और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच हुई बैठक में तय हो गया था, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चर्चा न होने के कारण इसकी घोषणा नहीं की गई थी। सोनिया गांधी ने कीर्ति आजाद से फोन पर बात करके उन्हें यह जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी दी थी। हालांकि दैनिक जागरण ने गुरुवार के अंक में 'पूर्व क्रिकेटर संभाल सकते हैं दिल्ली में कांग्रेस की पारी' शीर्षक से इस संभावना की खबर प्रकाशित की थी। इस खबर के बाद गुरुवार व शुक्रवार को भी दोनों दिन प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता लामबंद होते रहे और चाको व वेणुगोपाल से कीर्ति आजाद के नाम पर विरोध जताते रहे। इन सभी का कहना था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में बेहतर निर्णय यह होगा कि दिल्ली के ही नेता को यह जिम्मेदारी दे दी जाए। चाको और वेणुगोपाल की तरफ से यह संदेश सोनिया गांधी तक पहुंचाया भी गया, लेकिन पार्टी आलाकमान ने इस विरोध को कोई महत्व नहीं दिया।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर बाद चाको ने एक नोट बनाकर आलाकमान के हस्ताक्षर के लिए वेणुगोपाल के पास भेज दिया। इस नोट में प्रदेश अध्यक्ष के लिए दो नाम दिए गए थे। पहला नाम कीर्ति आजाद और दूसरा नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का था। सोनिया गांधी ने कीर्ति आजाद के नाम पर अपनी मुहर लगा दी।

कीर्ति आजाद भाजपा में रह चुके हैं और 1993 से 1998 तक गोल मार्केट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रहे हैं। इसके बाद भाजपा के ही टिकट पर बिहार के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से तीन बार सांसद भी रहे हैं। बाद में भाजपा में उपेक्षित महसूस किए जाने के कारण वह फरवरी 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर धनबाद से सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। अब उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर नई पारी खेलने का मौका दिया जाएगा, हालांकि वह कार्यभार कब संभालेंगे, इस बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

चाको को लिखे संदीप दीक्षित के पत्र पर अनुशासनात्मक समिति लेगी फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र व पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको को लिखे गए पत्र से पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। चाको ने उस पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी की अनुशासनात्मक समिति को पत्र सौंप दिया है। अब अनुशासनात्मक समिति इस मामले में कोई फैसला लेगी। दूसरी ओर शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे कई कांग्रेस नेताओं ने चाको पर निशाना साधा है। दिल्ली में कांग्रेस की बदहाली के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री की मौत की जांच कराने की भी मांग की है।

पत्र को लेकर दैनिक जागरण में शुक्रवार को खबर प्रकाशित होने के बाद पूर्व मंत्रियों व कई नेताओं ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री रमाकांत गोस्वामी, मंगत राम सिंघल, किरण वालिया ने प्रदेश प्रभारी पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित को कांग्रेस को मजबूत करने से रोका गया, जिससे वह परेशान थीं। प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने कहा कि शीला ने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था जिसे समय आने पर सार्वजनिक किया जाएगा।

> दिल्ली कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की राजनीति से मैं बाहर हूं और मेरा यहां कोई समर्थक नहीं है। मैंने पीसी चाको को व्यक्तिगत पत्र लिखा है। पत्र कैसे सार्वजनिक हुआ इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।'
> **-संदीप दीक्षित (पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र व पूर्व सांसद)**

> संदीप दीक्षित ने मुझे पत्र भेजा था जिसमें राजनीतिक बातें थीं, इसलिए उसे कांग्रेस अध्यक्ष के पास भेज दिया। पत्र में क्या लिखा गया है इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं।'
> **-पीसी चाको (दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रभारी)**

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संदीप दीक्षित का पत्र सार्वजनिक करना गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री की मौत की जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच और पार्टी के हित में प्रदेश प्रभारी को उनके पद से हटाना जरूरी है। इस मौके पर पार्टी के प्रवक्ता रोहित मनचंदा भी मौजूद थे।

न्यूज गैलरी

शरणार्थी परिवार के बच्चों को दाखिला न देने पर मांगा जवाब

नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परिवार के तीन बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला न दिए जाने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि तीन भाई-बहन संजिनी बाई (16), रवि कुमार (17) और मूना कुमारी (18) इस साल माता-पिता के साथ पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। इन बच्चों के पास पाकिस्तान के स्कूल से प्राप्त शिक्षा के प्रमाण पत्र हैं। ये बच्चे छतरपुर के भाटी माइंस स्थित सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल उनकी आयु ज्यादा बताकर दाखिला देने से मना कर रहा है। तीनों बच्चों ने दिल्ली सरकार से भी दाखिला दिलाने की अपील की थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों की ज्यादा उम्र को शिक्षा न देने का आधार कैसे बनाया जा सकता है? संबंधित अधिकारी पेश होकर जवाब दें। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। (जासं)

सात लाख से अधिक कीमत का बोंसाई पौधा

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुक्रवार को तीन दिवसीय ग्रीन शो कार्यक्रम का आगाज हुआ। यहां पहले दिन ही सात लाख 20 हजार की कीमत वाले बोंसाई पौधे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। यह पौधा 20 वर्ष पुराना है, जिसे घर के अंदर भी लगाया जा सकता है। पहले दिन लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर इस पौधे को निहारा। इस प्रदर्शनी में करीब 40 नर्सरी ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के 10 हजार पौधों की प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी में किचन गार्डनिंग वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कई प्रकार के पेड़-पौधों के बारे बताया जा रहा है। इसमें पौधों की खासियत से लेकर उनको बीमारियों से बचाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। (जासं)

ऑड-इवेन में सीएनजी वाहनों को छूट पर रेड सिग्नल

नई दिल्ली : ऑड-इवेन में किसे छूट मिले, इस पर दिल्ली सरकार द्वारा मांगी गई राय पर परिवहन विभाग ने तीन पेज की रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सीएनजी कारों को छूट नहीं दिए जाने की वकालत की गई है। रिपोर्ट शुक्रवार शाम परिवहन मंत्री को सौंप दी गई। मंत्री के माध्यम से यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी जाएगी। यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इसे मानती है या नहीं। परिवहन विभाग ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें सीएनजी से चलने वाली कारों को छूट देने से साफ मना किया गया है। विभाग ने इसके पीछे का कारण ऐसे वाहनों को लेकर लंबी निगरानी प्रक्रिया का होना बताया है। विभाग का कहना है कि महिलाओं को ऑड-इवेन से छूट दी जानी चाहिए। दोपहिया वाहनों को सुबह आठ बजे से 11 बजे तक छूट देने की बात है। सुझाव में यह बात नहीं कही गई है कि शाम को भी दोपहिया वाहनों को छूट मिले। कार्यालयों का समय सुबह 11 बजे से शाम साढ़े सात बजे तक किए जाने की बात कही गई है। (जासं)

रखी बात ▶ सीएम ने कोपेनहेगन में चल रहे सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया संबोधित

दुनिया को बताया, कैसे कम किया प्रदूषण

भविष्य में प्रदूषण को काबू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित सी-40 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली से संबोधित किया। इस दौरान दुनियाभर के देशों से पहुंचे महापौर को उन्होंने बताया कि दिल्ली में किस तरह प्रदूषण को कम करने में उन्हें सफलता मिली है। इसके साथ ही विश्व के अन्य शहरों के मेयर के साथ क्लीन एयर डिक्लेरेशन की घोषणा भी की है। इसमें पेरिस, लॉस एंजिल्स, कोपेनहेगन, बार्सिलोना और पोर्टलैंड के मेयर शामिल थे।

इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कोपेनहेगन जाना था। लेकिन विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्हें दौरा रद करना पड़ा था। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें अलग-अलग चरण में उन्होंने महापौरों के समक्ष अपनी बात रखी। इस बीच स्वच्छ हवा के लिए शहर के समाधान सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले चार साल में वायु प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दुनिया को दी। साथ ही इसमें जनता से मिले सहयोग को भी विस्तार से बताया। यही नहीं भविष्य में प्रदूषण को काबू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी।

दिल्ली सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोपेनहेगन में आयोजित सी-40 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वीडियो ग्रैब

केजरीवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वह कोपनहेगन आना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके। उन्हें बेहद खुशी है कि सी-40 की तरफ से क्लीन एयर सिटी के तौर पर शामिल 35 शहरों में दिल्ली भी शामिल है। पिछले चार साल में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में 25 फीसद प्रदूषण कम हो गया है। चार साल पहले दिल्ली प्रदूषण से लड़ रही थी। इसके बाद उन्होंने ऑड-इवेन लागू किया। इससे सड़कों से आधे वाहन कम हो गए। डीजल वाहनों पर रोक लगाई, थर्मल और कोयला आधारित पावर प्लांट बंद कराए गए। इसके अलावा इंडस्ट्री को सीएनजी आधारित किया गया। इसके लिए उन्हें मुआवजा दिया गया। इससे औद्योगिक प्रदूषण में कमी आई। पहले दिल्ली में पावर कट होता था। दो साल में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया, 24 घंटे बिना कट के बिजली मिलने से पांच लाख जनरेटर सेट बंद हुए। इससे भी प्रदूषण में कमी आई है।

हरियाली का दायरा बढ़ाया : मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर हरियाली का दायरा बढ़ाया गया। वायु की गुणवत्ता मापने के लिए कई जगह मॉनीटरिंग सिस्टम लगाए गए। इसके अलावा दिल्ली सरकार के हर निर्णय में दो करोड़ जनता का पूरा साथ मिला। कई सख्त निर्णय भी लिए गए, लेकिन लोगों का पूरा साथ मिला। जलवायु परिवर्तन से जुड़ा कोई भी बदलाव जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है।

सम्मेलन को इन्होंने भी किया संबोधित : पेरिस के मेयर ऐनी हिडाल्गो, लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक गार्सेटी, कोपेनहेगन के मेयर फ्रैंक जेनसेन, बार्सिलोना के मेयर अदा कोलैयू, पोर्टलैंड के मेयर टेड व्हीलर ,लीमा के मेयर जॉर्ज मुनोज वेल्स ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

सी-40 सम्मेलन को जानें : इसका पूरा नाम है सी-40 वर्ल्ड मेयर्स समिट है। तीन दिनी यह सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में चल रहा है। इसमें दुनिया भर के देशों के 90 से ज्यादा शहरों के मेयर भाग ले रहे हैं, जो करीब 70 करोड़ से अधिक नागरिकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन शहरों के प्रतिनिधि हरियालीयुक्त शहरी विकास पर एक-दूसरे के साथ अपने सुझाव साझा करते हैं। सी-40 शहरों के मेयर स्थानीय स्तर पर पेरिस समझौते के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सी-40 समूह 2005 में शुरू हुआ था। इसे लंदन के तत्कालीन मेयर केन लिविंग्स्टोन ने शुरू किया था। इसे सी- 40 नाम 2006 में दिया गया।

डीटीसी बसें घटी, कम हुए 20 करोड़ यात्री : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को बदहाल करने का आरोप लगाया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि बसों की कमी के कारण चार वर्षों में बस के 25 फीसद रूट बंद कर दिए गए हैं। वहीं छह माह में ही बसों के 12 सौ फेरे कम हो गए हैं। इससे बस यात्रियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ की कमी आई है। बंद किए गए बसों के मार्ग को फिर शुरू करने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। वह दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में प्रदूषण की समस्या हल करने को लेकर झूठे दावे कर रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ से हवा जहरीली हो रही है। इसके समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना होगा। यही नहीं डीटीसी की स्थिति दयनीय हो गई है। डीटीसी की बदहाली से सड़कों पर निजी वाहन बढ़ने के साथ ही यह महिला सुरक्षा के लिए भी गंभीर मामला है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सुरक्षित सफर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ही महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की घोषणा की गई है। बसों की कमी दूर किए बगैर मुफ्त यात्रा की घोषणा का कोई औचित्य नहीं है।

ये लगाए आरोप

- फरवरी, 2015 में बसों के कुल 574 मार्ग थे। अब इनकी संख्या घटकर 442 हो गई है यानी 132 रूट बंद कर दिए गए हैं।
- वर्ष 2015-16 के दौरान 129 .94 करोड़ यात्रियों ने डीटीसी बसों में सफर किया था। वर्ष 2018-19 यात्रियों की संख्या घटकर 110 करोड़ रह गई।

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में 11 हजार बसें होनी चाहिए। आप ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में पांच हजार नई बसें खरीदने का वादा किया था। इसके विपरीत बसों की संख्या कम हो गई है। वर्ष 2015 में डीटीसी की पांच हजार से ज्यादा बसें चल रही थीं। अब यह संख्या लगभग 37 सौ है। इनमें भी कई खराब रहती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में दिल्ली की आबादी और रिहाइशी क्षेत्र तो बढ़ा है, लेकिन बसों की संख्या कम हो गई है।

उन्होंने कहा कि छह माह में महत्वपूर्ण रूटों से लगभग डेढ़ सौ बसें हटाई गई हैं। इससे बसों के करीब 12 सौ फेरे कम हो गए हैं। उन्होंने बंद किए गए मार्ग फिर से शुरू करने और हटाई गई बसों चलाने की मांग की है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह, विधायक जगदीश प्रधान, पूर्व विधायक अनिल वाजपेयी व देविंदर सहरावत, दिल्ली भाजपा के मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बख्शी, अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।

भाजपा ने संपत्ति कर को लेकर खेला बड़ा दांव

निहाल सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं राजनीतिक दल लोगों को राहत देने वाली योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत और नियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति कर को लेकर आम माफी योजना की घोषणा की है। इसके बाद संपत्ति कर धारकों को बिना ब्याज और जुर्माने के बकाया संपत्ति कर जमा करने की छूट मिलेगी। इस योजना के दायरे में करीब पांच लाख संपत्ति कर धारकों के आने की उम्मीद है।

दरअसल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए संपत्ति कर आय का एक बड़ा स्रोत है। इससे निगम को पिछले वर्ष 666 करोड़ रुपये की आय हुई थी। निगम के अधिकार क्षेत्र में करीब 12 लाख संपत्ति करदाता हैं जिनमें से 4.46 लाख संपत्ति करदाता ही संपत्ति कर जमा करते हैं बाकि संपत्ति करदाताओं को संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए निगम ने यह आम माफी योजना की घोषणा की है।

शुक्रवार को स्थायी समिति की बैठक में नेता सदन तिलकराज कटारिया ने इस प्रस्ताव को स्थायी समिति की बैठक में रखा और इसे पारित कर दिया गया है। सत्ता पक्ष के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव के पारित होने के बाद इस प्रस्ताव को सदन से भी पारित कराना होगा।

> पिछले वित्तीय वर्ष में हमने आम माफी योजना की घोषणा की थी लेकिन लोगों की शिकायत थी कि उन्हें पता नहीं चल पाया इसलिए इस वर्ष फिर से आम माफी योजना लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
> **-तिलकराज कटारिया, नेता सदन उत्तरी निगम**

स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने कहा कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए स्थायी समिति ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है। जिसमें वर्ष 2004 से जिन संपत्तिधारकों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया है उसे बकाया संपत्ति कर पर लगने वाला ब्याज व जुर्माना नहीं देना होगा। वह केवल बकाया संपत्ति कर जमाकर सकेगा। वहीं जिसका 16 वर्ष का संपत्ति कर बकाया है वह चार वर्षों तक चार-चार वर्ष का संपत्ति कर किश्तों में जमा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी आम माफी लाने की घोषणा की थी। वहीं संपत्ति करदाता को यह भी सहूलियत दी गई है।

घर में जबरन घुसने के लिए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष दोषी करार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को एक बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुसने के लिए दोषी करार दिया है। अन्य आरोपितों को मारपीट करने के लिए भी दोषी करार दिया है। 2015 में एक बिल्डर के घर में जबरन घुसकर मारपीट करने का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अदालत ने गोयल को जबरदस्ती घर में प्रवेश करने के लिए दोषी ठहराया, जबकि सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता व बलबीर सिंह को मारपीट के लिए दोषी करार दिया। दोषियों की सजा पर अदालत में 18 अक्टूबर को जिरह होगी।

यह मामला छह फरवरी 2015 का है। रामनिवास गोयल और उनके समर्थकों ने विवेक विहार स्थित बिल्डर और नेता मनीष घई के घर पर चुनाव में बांटने के लिए शराब और कंबल के संदेह में छापेमारी की थी। घई ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई थी। इन आरोपों का खंडन करते हुए गोयल ने कहा था कि उन्होंने ही पहले पुलिस को इस बारे में कॉल करके सूचना दी थी। वह पुलिस के साथ ही घई के घर गए थे। दूसरी ओर घई का आरोप था कि दोषियों ने उनके घर में अलमारी, ड्रायर, रसोई का सामान, खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए थे।

उद्घाटन के सात माह बाद हिंडन से उड़ा पहला विमान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दिल्ली-एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट हिंडन पर उद्घाटन के सात माह बाद शुक्रवार को पहले विमान ने उड़ान भरी। एयर हेरिटेज का नौ सीटर विमान दोपहर अपने निर्धारित समय एक बजे के बदले करीब सवा घंटे की देरी से दोपहर 2:20 बजे हिंडन से रवाना हुआ। पिथौरागढ़ के लिए सफर कर रहे यात्रियों ने सेवा शुरू होने पर सरकार को धन्यवाद कहा। उधर, पिथौरागढ़ के लिए ही एक माह में एक और फ्लाइट और शिमला के लिए फ्लाइट दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि हिंडन से पिथौरागढ़ का प्रति व्यक्ति किराया 2270 रुपये, जबकि पिथौरागढ़ से हिंडन तक का प्रति व्यक्ति किराया 2470 रुपये है।

उल्लेखनीय है कि हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ मार्च को किया था। करीब सात माह बाद शुक्रवार को एयरपोर्ट से पहले विमान को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री वीके सिंह, केंद्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टम्टा और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग समेत अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिथौरागढ़ से निर्धारित समय दोपहर साढ़े बारह बजे हिंडन पर विमान को पहुंचना था, लेकिन कम दृश्यता के चलते वहां से नौ यात्रियों को लेकर करीब सवा घंटे देरी से विमान उड़ा।

विमान की सभी नौ टिकटें पहले ही बुक हो चुकी थीं। दोपहर करीब 12 बजे यात्रियों ने चेक-इन करना शुरू कर दिया। सबसे पहली यात्री दिल्ली निवासी रीना हुसैन ने चेक-इन किया। सवा 12 बजे तक सभी यात्री पहुंच गए थे। हालांकि यात्रियों को कुछ देर बाद सूचना दी गई कि विमान करीब एक घंटे देरी से उड़ेगा। यात्रियों ने इस दौरान वेटिंग रूम में इंतजार किया।

त्रिवेंद्र रावत बोले, पिथौरागढ़ से एनसीआर का जुड़ना देश की सामरिक ताकत के लिए महत्वपूर्ण

सौरभ पांडेय, गाजियाबाद

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए पहले विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ से दिल्ली-एनसीआर का जुड़ना न सिर्फ आम जनता, बल्कि देश की सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। नेपाल और तिब्बत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ने के सामरिक लाभ भी होंगे। महज चार रुपये प्रति किलोमीटर के खर्च में हवाई सफर करा रही उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना ने प्रधानमंत्री के हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर कराने के सपने को साकार कर दिया है। उधर, दिल्ली से लखनऊ लौट रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंडन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। त्रिवेंद्र रावत ने उड़ान से पहले पहली फ्लाइट में यात्रा कर रहे यात्रियों को बोर्डिंग पास सौंपते हुए स्वागत किया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड की खूबसूरती हर कोई देखना चाहता है, लेकिन पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर जाने के लिए लोगों को 14-16 घंटे लगते थे। अब महज एक घंटे में सफर पूरा होगा, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

पिथौरागढ़ से आने वाले यात्रियों का स्वागत करते त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य मंत्री। जागरण

अध्ययन

एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने 350 लोगों पर किया शोध, सामने आया कि प्रदूषण से गठिया पीड़ित लोगों की बढ़ जाती है समस्या

हर पांचवें व्यक्ति को गठिया होने का खतरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

गठिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए दैनिक कार्य कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। चिंताजनक यह है कि दिल्ली में स्वस्थ दिखने वाले 20 फीसद लोगों के खून में ऐसे कारक पाए गए हैं, जिनसे गठिया की बीमारी हो सकती है। ऐसे में यहां के हर पांचवें व्यक्ति को कुछ वर्षों बाद गठिया होने का खतरा है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई है।

संस्थान के रूमेटोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने 350 लोगों पर यह शोध किया है। इनमें से 29 फीसद लोगों की उम्र 18 से 30 वर्ष थी। वहीं 35 फीसद लोग 31-40 वर्ष, 27 फीसद लोग 41-50 वर्ष व नौ फीसद लोग 51-60 वर्ष की उम्र के थे। रूमेटोलॉजी की विभागाध्यक्ष डॉ. उमा कुमार ने कहा कि इस शोध में यह देखने की कोशिश की गई है कि वायु प्रदूषण, ऑटोइम्यूनिटी व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या जुड़ाव है। इसलिए अध्ययन में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो 10 साल से अधिक समय से दिल्ली में रह रहे हैं। साथ ही जिनमें गठिया या किसी ऑटोइम्यून रोग का कोई लक्षण नहीं है। उनके खून के सैंपल लेकर तीन तरह की ऑटो एंटिबॉडी (आरएफ, एएनए, एएनटीआइ-सीसीपी) की जांच की गई। ये ऐसे मार्कर हैं जो यदि शरीर में मौजूद हों तो ऑटोइम्यूनिटी विकसित होने लगती है। इस वजह से शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान होने लगता है। 20 फीसद लोगों में सब-क्लीनिकल ऑटोइम्यूनिटी पाई गई है। यह ऐसी स्थिति है जब लोगों को वर्तमान समय में गठिया या कोई ऑटोइम्यून रोग तो नहीं होता, लेकिन 15 से 20 सालों में यह बीमारी में तब्दील हो सकती है। डॉक्टर इसका बड़ा कारण वायु प्रदूषण मान रहे हैं। इससे पहले एम्स में हुए शोध में यह बात साबित हो चुकी है कि प्रदूषण होने पर गठिया पीड़ित लोगों की समस्या बढ़ जाती है।

जोड़ों में हो दर्द तो न करें नजरअंदाज : डॉक्टर कहते हैं कि शरीर के जोड़ों में लंबे समय तक दर्द रहे तो उसे नजरअंदाज न करें। गठिया की बीमारी से युवा अधिक पीड़ित हो रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं में यह बीमारी अधिक होती है। जोड़ों में दर्द, सूजन, कामकाज में परेशानी होना, सो कर जगने पर हाथों में आधे घंटे तक जकड़न रहे तो यह गठिया की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।

जीवनशैली में बदलाव जरूरी : प्रदूषण, धूमपान, लंबे समय तक कंप्यूटर व स्मार्ट फोन पर काम करने से जोड़ों में दर्द व गठिया की बीमारी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर जीवनशैली में बदलाव करने की जरूरत बता रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि धूमपान न करें। कंप्यूटर पर अधिक देर तक बैठकर लगातार काम न करें। इसके अलावा स्मार्ट फोन पर अधिक टाइपिंग करने से बचना चाहिए।

जोड़ों में हर दर्द नहीं होती गठिया की बीमारी : डॉक्टर कहते हैं कि जोड़ों में दर्द होने पर जरूरी नहीं कि वह गठिया की ही बीमारी हो। दर्द का एक बड़ा कारण विटामिन डी की कमी होना है। एम्स में हुए अध्ययन में यह बात समाने आई है कि 50 फीसद लोगों में विटामिन डी की ज्यादा कमी है। 41 फीसद लोगों में विटामिन डी की थोड़ी कमी पाई गई। सिर्फ 9 फीसद लोगों में विटामिन डी सामान्य है।

मांसपेशियों में दर्द भर रहा बस्ते का बोझ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

बस्ते का बोझ स्कूली बच्चों की मांसपेशियों व हड्डियों को कमजोर कर रहा है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा किए गए अध्ययन में सरकारी स्कूलों के 63 फीसद छात्र मांसपेशियों व हड्डियों (मस्कुलोस्केलेटल) के दर्द से पीड़ित मिले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बच्चों का भारी बस्ता सामने आई है। इसके अलावा देर तक टीवी देखने व स्मार्ट फोन भी बच्चों की हड्डियों में दर्द की वजह बन रहा